इकाई 13 वैश्वीकरण पर बदलते दृष्टिकोण *

संरचना

13.0 उद्देश्य

13.1 प्रस्तावना

13.2 वैश्वीकरण : अवधारणा और अर्थ

13.3 वैश्वीकरण के विभिन्न परिप्रेक्ष्य

13.3.1 अर्थशास्त्रिक परिप्रेक्ष्य

13.3.2 बहुआयामी परिप्रेक्ष्य

13.3.3 विश्व–नागरिक परिप्रेक्ष्य

13.4 वैश्वीकरण के प्रति दृष्टिकोण

13.5 वैश्वीकरण का प्रभाव

13.5.1 वैश्वीकरण और श्रम

13.5.2 वैश्वीकरण और पर्यावरण

13.5.3 वैश्वीकरण और विश्व की गरीबी

13.6 सारांश

13.7 शब्दावली

13.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें

13.9 बोध प्रश्नों के उत्तर अथवा संकेत

13.0 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई का अध्ययन करने के बाद आप इस योग्य होंगे कि –

- वैश्वीकरण के विभिन्न परिप्रेक्ष्य स्पष्ट कर उन पर चर्चा कर सकें;
- वैश्वीकरण के प्रति तीन दृष्टिकोणों की व्याख्या कर सकें; तथा
- वैश्वीकरण के प्रभाव को पहचान सकें।

13.1 प्रस्तावना

वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है। इस शब्द की जटिलता के कारण इसकी कोई एक परिभाषा देना कठिन है। इसे एक ऐसे शब्द के रूप में समझा जा सकता है जो यह

* डॉ. निधि तेवतिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, सामाजिक विज्ञान विद्यापीठए इग्नू कृत

दर्शाता है कि सभी राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियाँ एक स्तर पर पर संचालित होती हैं, यथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर। हम सभी ने वैश्विक स्तर पर जुड़ने वाले लोगों और समुदायों में अप्रत्याशित और तीव्र वृद्धि देखी है। विभिन्न अनुप्रयोगों के माध्यम से नई तकनीक का उपयोग कर संचार के उपलब्ध मंच के कारण विभिन्न लोगों, समुदायों और संस्कृतियों के बीच भौतिक दूरी कम हो गई है। यह इकाई वैश्वीकरण की अवधारणा के बोध, वैश्वीकरण के विभिन्न परिप्रेक्ष्य, वैश्वीकरण के प्रति विभिन्न दृष्टिकोण और वैश्वीकरण के प्रभाव पर एक सामान्य चर्चा प्रस्तुत करती है।

13.2 वैश्वीकरण : अवधारणा और अर्थ

आजकल वैश्वीकरण (globalisation) शब्द का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, इसका उपयोग सामाजिक विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में, पत्रकारिता जैसे व्यवसाय में और जनप्रिय संलाप में किया जाता है। फिर भी इसका व्यापक उपयोग अभी तक वैश्वीकरण की ऐसी कोई परिभाषा नहीं दे पाया है जो विश्व स्तर पर स्वीकृत हो। बहरहाल, ऐसा लगता है कि हर कोई इस बात से सहमत है कि यह सामाजिक परिवर्तन की एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति या देश के जीवन के विभिन्न आयामों को प्रभावित करती है। किंतु इस प्रक्रिया की प्रकृति और वैश्वीकरण के प्रभाव हमेशा तर्क–वितर्क और वाद–विवाद के विषय रहे हैं।

वैश्विक परिवर्तन की प्रकृति की विभिन्न व्याख्याएँ जो ऐसे वाद–विवाद के परिणामस्वरूप सामने आती हैं, सामाजिक विज्ञान की विभिन्न विद्याशाखाओं के दृष्टिकोण से वैश्वीकरण के विभिन्न परिप्रेक्ष्य दर्शाती हैं। वैश्वीकरण पर अर्थशास्त्रियों, समाजशास्त्रियों और राजनीतिक वैज्ञानिकों के विचार वैश्वीकरण के विभिन्न आयामों पर जोर देते हैं। वैश्वीकरण के विषय में इस प्रकार के विचारों के कारण ही इस शब्द का आकलन और मूल्यांकन भिन्न–भिन्न प्रकार से किया जाता है। आइए, वैश्वीकरण की अवधारणा के उद्‌भव और इसके सामाजिक विज्ञान में व्यवहार पर कुछ विस्तार से चर्चा करें।

वर्तमान में वैश्वीकरण शब्द का प्रयोग रोजमर्रा की बातचीत में भरपूर किया जाता है। इसको यह लोकप्रियता सन 1990 के दशक में हासिल हुई थी। किंतु सामाजिक विज्ञान की विभिन्न विद्याशाखाओं में इसका प्रयोग इस दशक से अनेक वर्ष पूर्व से ही किया जाता रहा है।

जैन स्कोल्ट (2000) के अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पहली बार सामाजिक विज्ञान में इस शब्द का प्रयोग किया गया था। मुख्यतः इस शब्द का प्रयोग वैश्विक आर्थिक आदान–प्रदान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया गया था। संचार प्रौद्योगिकी में नवाचार ने एक 'वैश्विक गाँव' बनाना शुरू कर दिया क्योंकि इस प्रकार के नवाचार ने आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अंतर्क्रियाओं के परावर्तक परिणामों के साथ समग्र संसार में सूचना के प्रवाह को तेजी से आगे बढ़ाया।

वैश्विक गाँव (global village) का अर्थ इस लिहाज से लिया गया कि वैश्विक गाँव में रहने वाले लोगों का एक सामान्य वैश्विक दृष्टिकोण होगा, जो कि पहचान परिवर्तक (identity changer) के रूप में कार्य करेगा।

ऐसी स्थिति में, यह मान लेना आम बात थी कि एक वैश्विक नागरिक समस्त मानव जाति की एकता दर्शाती वैश्विक चेतना के साथ उभरेगा। इस पूरे प्रकरण ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिदृश्य को प्रभावित किया क्योंकि इसने विभिन्न देशों की बढ़ती परस्पर निर्भरता और एक वैश्विक बाजार के उदय पर जोर दिया। इस प्रकार के परिवर्तन संचार, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, शासन और राजनीतिक व्यवस्था जैसे क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं।

एबरडीन विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रोफेसर रोलैंड रॉबर्टसन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वैश्वीकरण को 'संसार के बोध और सकल संसार के बढ़ते अवबोधन' के रूप में परिभाषित किया।[1] .समाजशास्त्री मार्टिन एल्ब्रो और एलिजाबेथ किंग वैश्वीकरण को इन शब्दों में परिभाषित करते हैं – 'वे सभी प्रक्रियाएँ जिनके द्वारा संसार भर के लोगों को किसी एकल विश्व समाज में शामिल किया जाता है'।[2] इस प्रकार, हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण राष्ट्रों, संस्कृतियों और विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक संरचनाओं के बीच संचार विषयक है। इसके लिए बाजार, सरकारों और समाज की भूमिकाओं और दायित्वों के पुनर्विरचन और पुनर्गठन की आवश्यकता होती है।

13.3 वैश्वीकरण के विभिन्न परिप्रेक्ष्य

वैश्वीकरण बहुआयामी है और इसीलिए विभिन्न विद्याशाखाओं के सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा इसके विभिन्न आयामों का अध्ययन और उनमें अंतर स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। वैश्वीकरण के विभिन्न आयामों को आर्थिक और गैर–आर्थिक आयामों में विभाजित किया गया है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया, वैश्वीकरण अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिवर्तनों से संबंध रखता है, परंतु वैश्वीकरण संचार, संस्कृति, प्रवास, राजनीति और समकालीन जीवन के कई अन्य पहलुओं पर प्रभाव डालने से भी संबंध रखता है। इनके अलावा, वैश्वीकरण उन अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संबंधों को भी प्रभावित करता है जो

---

[1] रॉबर्टसन, रोलैंड (1992), *ग्लोबलाइजेशन : सोशल थ्योरी एंड ग्लोबल कल्चर* (पुनर्मुद्रण, सं.), लंदन : सेज, ISBN 0803981872.

[2] एल्ब्रो, मार्टिन और एलिजाबेथ किंग (सं.) (1990), *ग्लोबलाइजेशन, नॉलेज एंड सोसाइटी*, लंदन : सेज, ISBN 978&0803983243.

अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को आकार देते हैं और विश्व भर में सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों को प्रभावित करते हैं। वैश्वीकरण में वैश्विक पूँजीवाद की सर्वोच्च विशेषताएँ हैं। एकध्रुवीयता के समर्थक इस बात पर बल देते हैं कि वैश्वीकरण मानव जाति को लाभान्वित कर सकता है क्योंकि यह उनके मूल्यों, संस्थाओं और विश्व–दृष्टिकोण प्रचार–प्रसार करता है। वैश्वीकरण के विश्लेषणात्मक और नियामक पहलुओं को विभिन्न दृ ष्टिकोणों द्वारा स्पष्ट किया जाता है। इन दृष्टिकोणों में अंतर नीतिगत हस्तक्षेपों में अंतर पैदा करता है, जो कि बदले में वैश्वीकरण प्रक्रिया के कल्याण और न्याय परिणामों को प्रभावित करता है।

13.3.1 अर्थशास्त्रिक दृष्टिकोण

अर्थशास्त्रिक परिप्रेक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक आदान–प्रदान की बढ़ती आवृत्ति, विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक निर्भरता और उनके एकीकरण की सुविधा में वृद्धि पर बल देता है। ऐसा कहा जाता है कि विश्व सर्वव्यापक अंतर्जात आर्थिक नीति दृष्टिकोण की ओर बढ़ रहा है, जिसका आधार बहिर्मुखी विकास मॉडल में है। इस प्रकार का मॉडल अंतर्राष्ट्रीय निवेश और पूँजी एवं व्यापार के प्रवाह पर निर्भर होता है। इससे केन्जियन अर्थशास्त्र और केंद्रीकृत आर्थिक नियोजन मॉडल का अंत हो जाएगा।

वर्ष 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में समझौते पर हस्ताक्षर करने वालों को आशा थी कि वे सोने के मानक की पुनर्पुष्टि करके सन 1930 के दशक की महामंदी जैसी वित्तीय अस्थिरता से बच जाएँगे। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय पूँजीवादी व्यवस्था का सुचारु संचालन ही था। तथापि, प्रभाव का सामना उस विकास मॉडल द्वारा किया गया जिसे फिर शीघ्र ही छोड़ दिया गया था, यथा अंतर्जात आर्थिक विकास मॉडल। तदंतर वर्ष 1995 में ही कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन अस्तित्व में आ पाया, यथा विश्व व्यापार संगठन (WTO)। इससे पूर्व कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विशेषकर व्यापार के लिए, बनाने के किसी भी प्रयास को स्थगित कर दिया जाता रहा था।

वस्तुतः वर्ष 1995 तक बढ़ते आर्थिक विनिमय और अन्योन्याश्रितता के कारण अंतर्जात मॉडल की प्रासंगिकता कम हो चली थी। वर्ष 1971 में स्वर्ण मानक को निरस्त कर दिया गया, जिससे वित्तीय पूँजी का अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह आसान हो गया। इसका पूर्वी एशियाई देशों पर प्रभाव पड़ा, जिन्होंने कम लागत वाले श्रम की उपलब्धता के कारण अपने निर्यात में वृद्धि का अनुभव किया।

ऐतिहासिक रूप से कई ऐसी घटनाएँ हुई हैं जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रकट करती हैं, यथा –

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक पर संयुक्त राज्य अमेरिका की मजबूत पकड़।
- अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का विनियमन
- वैश्विक व्यापार की मात्रा में वृद्धि
- बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए नए अवसर
- पहले से अधिक प्रायिक आउटसोर्सिंग और उत्पादन का स्थान परिवर्तन
- सोवियत संघ का विघटन
- पूर्व साम्यवादी देशों में बाजार उदारवाद को अपनाया जाना
- चीन द्वारा वैश्विक आर्थिक बाजार का विस्तार

अर्थशास्त्रियों का मानना है कि वैश्विक बाजार ने निम्नलिखित योगदान दिया है –

- अनेक कम आय वाली विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा किया।

- उच्च आय वाले देशों को निर्यात के लिए माल के उत्पादन से जीवन स्तर में वृद्धि हुई है।
- उद्यमियों के लिए नए अवसर पैदा किए ।
- पश्चिमी देशों में रोजगार को बढ़ावा दिया।

कुल मिलाकर परिणाम दोनों पक्षों की जीत की स्थिति जैसा प्रतीत होता है, जिसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था में भाग लेने वालों के जीवन स्तर में नाटकीय रूप से वृद्धि होती है। बहरहाल, इन दावों को शिक्षाविदों, नीति–निर्माताओं, मजदूर संघ के नेताओं जैसे कई समूहों द्वारा व्यापक रूप से चुनौती दी गई है।

बाहरी ठेका दिए जाने अर्थात् आउटसोर्सिंग और औद्योगिक उत्पादन के स्थान परिवर्तन के कारण कई लोगों की नौकरी भी चली गई। इसलिए, हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण से अंततः समस्त मानव जाति को लाभ नहीं होगा। यह माना जाता है कि आर्थिक दृष्टिकोण संकीर्ण है और यह वैश्वीकरण प्रक्रिया के जटिल बहुआयामी अभिलक्षणों पर विचार नहीं करता है और न ही उनका प्रग्रहण करता है।

13.3.2 बहुआयामी परिप्रेक्ष्य

वैश्वीकरण की प्रक्रिया केवल आर्थिक नहीं है। समाजशास्त्री बताते हैं कि वैश्वीकरण तकनीकी, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक भी है। जो लोग आर्थिक परिप्रेक्ष्य की आलोचना करते हैं वे अब भी इस बात से सहमत हैं कि वैश्वीकरण की प्रेरक शक्ति मुख्य रूप से आर्थिक ही है। तथापि, वे यह भी विचार करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विनिमय, अन्योन्याश्रितता और एकीकरण को बढ़ावा देने में संचार प्रौद्योगिकी में विकास, आप्रवासन प्रतिमान और राजनीतिक संबंध एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी की भूमिका का प्रमुख योगदान रहा है। जनसंचार माध्यमों में प्रौद्योगिकी–आधारित नवाचार के कारण ही विश्व भर में लाखों लोग दुनिया भर की घटनाओं से अवगत हो पाए हैं। इस तरह के प्रदर्शन का परिणाम यह हुआ है कि लोग अब विविध संस्कृतियों और जीवन शैलियों के विषय में अधिक भिज्ञ हैं।

कई देशों के लोगों के बीच पारस्परिक संपर्क में वृद्धि हुई है। यात्रा में वृद्धि हुई है और इंटरनेट ने लोगों को तत्काल उन लोगों के साथ बातचीत करने की सुविधा दी है जो अन्य क्षेत्रों में दूरवर्ती स्थानों पर रहते हैं। वैश्वीकरण ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक कलाकृतियों के उपभोग को भी आसान बना दिया है। एक साधारण व्यक्ति के लिए दूसरे देश के व्यंजन, कला, संगीत और परिधान का उपभोग करना आसान हो गया है। यह दरअसल विविध संस्कृतियों का प्रचार–प्रसार ही है। फिर भी यह प्रसार कई वैश्वीकरण विद्वानों के लिए बहस का विषय है क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं है कि प्रसार वास्तव में हो रहा है।

प्रवासन कोई नई अवधारणा नहीं है, फिर भी हाल के दशकों में निम्न से उच्च आय वाले देशों में प्रवास का विस्तार यह बताता है कि यह वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण आयाम है। पश्चिमी देश ग्लोबल साउथ से बहुत से लोगों को आकर्षित करते हैं। तकनीकी कौशल

वाले सुशिक्षित लोग नए प्रवासियों का एक बड़ा हिस्सा हैं। समरूप संस्कृतियाँ बहुत जटिल और विविध होती जा रही हैं।

बहुपक्षीय संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते राजनीतिक सहयोग और नागरिक समाज की गतिविधियों के विकास को बढ़ावा दे रहे हैं। यह भी वैश्वीकरण प्रक्रिया का एक पहलू है क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और पारस्परिकता में योगदान देता है। वैश्विक नागरिक समाज का प्रादुर्भाव हुआ है, जिसके माध्यम से आम लोग भी अपना प्रभाव डालने में सक्षम हुए हैं।

वैश्विक नागरिक समाज का उपयोग करने और उसका हिस्सा बनने के लिए हर व्यक्ति के लिए विभिन्न डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं। राष्ट्र राज्य की अवधारणा अभी भी प्रासंगिक है क्योंकि राष्ट्र राज्यों के आने वाले कई दशकों तक मौलिक सामाजिक और राजनीतिक संरचनाओं के रूप में काम करने की संभावना है। वैश्वीकरण इन राष्ट्र राज्यों के लोगों के एक–दूसरे के साथ संबंध बनाने और अंतर्क्रिया के तरीके में महत्वपूर्ण बदलाव लाया है। लोगों में अब अपनी सर्वनिष्ठ मानवता संबंधी साझा वैश्विक चेतना जागी है।

13.3.3 विश्व–नागरिक परिप्रेक्ष्य

विश्व–नागरिक परिप्रेक्ष्य इस सिद्धांत पर जोर देता है कि सभी मनुष्य एक वैश्विक समुदाय के सदस्य हैं। विश्व नागरिकों का मानना है कि विभिन्न समाजों के एकीकरण को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक, धार्मिक एवं राष्ट्रीय मतभेदों को दूर करने के लिए केन्द्रीकृत प्रयास किए जाने चाहिए। वैश्वीकरण इन आदर्शों का बोध करने में सक्षम कर सार्वभौमिकता के अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है। विश्व नागरिक (cosmopolitan) पदबंध का प्रयोग मोटे तौर पर एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था के लिए किया जाता है जो राष्ट्र राज्य से कहीं बढ़कर है।

इस पदबंध का प्रयोग उस दृष्टिकोण को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है जो सीमित राष्ट्रीय निष्ठाओं एवं पूर्वाग्रहों को स्वीकार नहीं करता और विभिन्न राष्ट्रों के लोगों के बीच समानताएँ पहचाने जाने को बढ़ावा देता है। यह सर्वदेशीय दृष्टि बहुपक्षीय, संस्थागत व्यवस्थाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करती है, जो कि विश्व भर के राष्ट्र राज्यों के बीच सहयोग को सुगम बनाता है। मानव कल्याण और सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने के लिए विश्व–नागरिक परिप्रेक्ष्य यह अवधारणा प्रस्तुत करता है कि विश्व के राष्ट्र राज्य बहुपक्षीय संस्थानों, अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवाधिकार सम्मेलनों के माध्यम से सहयोग कर सकते हैं। इस प्रकार के विश्वबंधुत्व की जड़ें आमतौर पर कांटियन अवधारणा से मान्यता प्राप्त हैं कि शांति के संरक्षण के प्रति समर्पित संप्रभु राष्ट्र राज्यों का गठबंधन बनाने के लिए सामाजिक समझौते को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जा सकता है।

प्रथम विश्व युद्ध के नरसंहार ने कई देशों को प्रभावित किया था। अतः अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति की रक्षा के लिए बेहतर प्रयास किए जाने आवश्यक थे। लीग ऑफ नेशन्स की विफलता के बावजूद वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र के रूप में उसके पुनरुद्धार ने उदारवादी विश्वबंधुत्व को सक्रिय किया। इसके अलावा, मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को अपनाने, राष्ट्रीय न्यायपालिकाओं द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों का नियमित

सहारा लिए जाने तथा विश्व न्यायालय (International Court of Justice) और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court) जैसी अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक संस्थाओं के गठन ने उदारवादी विश्वबंधुत्व को और मजबूत किया। तदोपरांत यूरोपीय आर्थिक समुदाय (European Economic Community) के गठन और एक अर्ध–राजनीतिक संघ के रूप में इसके तदंतर पुनर्निर्माण ने विश्व–नागरिक आदर्शों को और ताजा कर दिया।

उदारवादी विश्वबंधुत्व के समर्थक वैश्वीकरण को वैश्विक शांति, एकीकरण और अन्योन्याश्रितता के लक्ष्य प्राप्त करने के साधन के रूप में देखते हैं। वैश्वीकरण होने के साथ लोग और उनकी सरकारें तेजी से पहचानती जा रही हैं कि वे एक समान मानव समुदाय के सदस्य हैं।

इन देशों को सहयोग से बहुत कुछ हासिल करना है और इस कारण वे सब के लिए सामाजिक कल्याण एवं सामाजिक न्याय का समर्थन करते हुए वैश्वीकरण की शक्तियों को विनियमित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। इस परिप्रेक्ष्य का प्रमुख तत्व यह विश्वास है कि वैश्वीकरण की शक्तियों को मानवीय हित साधे जाने के लिए नियंत्रित किया जा सकता है। यह परिप्रेक्ष्य विद्यमान बहुपक्षीय व्यवस्थाओं को मजबूत करने अथवा नई व्यवस्थाएँ बनाने के लिए विभिन्न प्रस्तावों को व्यक्त करता है, जो कि राष्ट्रों के लिए वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक कार्यप्रणालियों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन कर सकें। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय संघों एवं संगठनों को पुनर्जीवित करने और कुछ नए गठित किए जाने से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा तथा वैश्वीकरण की चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी।

इन प्रस्तावों को एक सामाजिक लोकतांत्रिक ढाँचे के भीतर संकुलित किया गया है, जो कि उदारवादी विश्वबंधुत्व के आदर्शों को ही दर्शाता है। उदीयमान नागरिक–समाज संस्थाओं की भूमिका में बढ़ते विश्वास के साथ ही वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है।

हाल के दिनों में नए और सुधारित बहुपक्षीय संस्थानों के लिए प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का भी सुझाव दिया गया है। हाल के दिनों में नयी और उन्नत बहुपक्षीय संस्थाओं के लिए प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का भी सुझाव दिया गया है। इन प्रस्तावों की वैश्विक शक्ति में मौजूदा असमानताओं और एकध्रुवीय विश्वासों के आधिपत्य के आलोक में आलोचना के लिए जाना जाता है। इन प्रस्तावों को वैश्विक शक्ति में अभिभावी असमानताओं और एकध्रुवीय मान्यताओं के आधिपत्य के आलोक में अपनी आलोचना के लिए जाना जाता है।

13.4 वैश्वीकरण के प्रति दृष्टिकोण

पिछले पाठांश में की गई चर्चा से हम देखते हैं कि वैश्वीकरण पर चर्चाओं के भीतर तीन भाव या अर्थ धीरे–धीरे उभरे हैं – स्थानांतरण, परिवर्तन और पारगमन। समकालीन वैश्वीकरण का एक मूल दावा यह है कि अब राष्ट्र राज्य की अवधारणा (राष्ट्र राज्य एक स्वतंत्र देश होता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग समान भाषा, परंपराओं और इतिहास को साझा करते हैं) व्यवहारातीत हो गई है।

वैश्वीकरण के कारण किसी राष्ट्र की सीमाएँ अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं रहीं जितनी वे पहले हुआ करती थीं। बहरहाल, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसको किस दृष्टिकोण को देखते हैं क्योंकि वैश्वीकरण के तीन अलग–अलग दृष्टिकोण हैं, यथा –

- अंतर्राष्ट्रीयवादी दृष्टिकोण
- परिवर्तनवादी दृष्टिकोण
- ग्लोबलिस्ट दृष्टिकोण

अंतर्राष्ट्रीयवादियों (internationalists) के अनुसार वैश्वीकरण एक मिथक है। उनका मानना है कि अधिकांश आर्थिक और सामाजिक गतिविधियाँ वैश्विक स्तर पर नहीं बल्कि क्षेत्रीय स्तर पर चलती हैं। विश्वव्यापी व्यापार के मोर्चे पर वे इस बात पर जोर देते हैं कि अधिकांश विनिमय वैश्विक की बजाय क्षेत्रीय स्तर पर होता है। यूरोपीय संघ, प्रशांत घेरा व अन्य व्यापार गुट उदाहरण के रूप में कार्य करते हैं। उनका मानना है कि वैश्विक पूँजीवाद के तर्क ने विकसित और विकासशील देशों के बीच अधिक ध्रुवीकरण किया है। उनका मानना है कि वैश्वीकरण आधुनिक दुविधाओं का सामना करने के लिए राज्य की भूमिका का विस्तार कर देता है।

परिवर्तनवादियों (transformanationalists) के अनुसार राष्ट्र राज्य शक्तिशाली बना रहता है और जो भी चुनौतियाँ होती हैं उनका पुनर्गठन, सुधार एवं वैश्विक शासन के नए रूपों को समायोजित करके सामना किया जा सकता है। सरकारें पूरी तरह से सत्ता खोने के बजाय अपनी भूमिकाओं को समायोजित कर सकती हैं। चूँकि नया वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य उभर रहा है, हम यह नहीं मान सकते हैं कि वैश्विक निर्णय लेने में सभी सरकारों की बराबर की हिस्सेदारी होगी। विश्व भर में सबसे गरीब सरकारों का वैश्विक निर्णय लेने में बहुत कम योगदान है।

संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान एक साथ काम कर सकते हैं और कुछ अन्य देशों की उपेक्षा की जाएगी, मुख्यतः गरीब देशों की। यह मुख्य रूप से इसलिए होगा कि सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं के पास गरीब देशों की तुलना में अधिक राजनीतिक शक्ति है। यूनाइटेड किंगडम के मामले में राष्ट्र राज्य अभी भी बहुत महत्वपूर्ण है। यूनाइटेड किंगडम सरकार को अन्य देशों पर विचार करने के लिए समायोजन करना पड़ सकता है, परंतु चूँकि इनमें से अधिकांश देश यूरोपीय संघ के भीतर ही हैं, ऐसा लगता है कि यूनाइटेड किंगडम सरकार वैश्वीकरण की तुलना में अधिक क्षेत्रीय होती जा रही है।

यूनाइटेड किंगडम सरकार को वैश्विक स्तर से कहीं अधिक स्थानीय स्तर पर अपनी भूमिकाएँ बदलनी पड़ी हैं। यह दावा कि वैश्वीकरण ने राष्ट्र राज्य को व्यवहारातीत बना दिया है, सच नहीं लगता है क्योंकि अधिक संभावना यह है कि यूरोपीय संघ जैसे संघों के भीतर राष्ट्र राज्य को फिर से आकार दिया जा रहा है, हालाँकि वैश्विक स्तर पर नहीं।

देशों के बीच सहयोग और आपसी समझ में तेजी से वृद्धि हुई है। इससे विश्व भर में अंतरसरकारी संगठनों की संख्या में नाटकीय वृद्धि हुई है। इनमें से प्रत्येक संगठन में प्रत्येक देश के प्रतिनिधि मौजूद होते हैं, जो कि वास्तव में उस राष्ट्र राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे वे आते हैं। विश्व भर में मानव जाति को जोड़ने वाले संचार और संगठनों के विकास को वैश्वीकरण द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। चूँकि लोगों के बीच संचार और

अंतर्क्रिया उनकी राष्ट्रीय सीमाओं से निरुद्ध नहीं होते, वैश्वीकरण का अर्थ यह नहीं है कि एक राष्ट्र राज्य अपनी संप्रभुता खो देता है। परिवर्तनवादी रुख वैश्वीकरण के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह वैश्विक प्रवृत्तियों के अस्तित्व का विरोध करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उससे उत्पन्न होने वाली दुविधाओं का सामना करने का प्रयास करता है।

ग्लोबलिस्ट दृष्टिकोण रखने वाले लोग (globalists) वैश्वीकरण को एक अपरिहार्य प्रक्रिया के रूप में देखते हैं और दावा करते हैं कि दुनिया ने 'वैश्विक पूँजीवाद' के प्रभुत्व को वैध बनाने के लिए वास्तव में वैश्विक युग में प्रवेश किया है। ग्लोबलिस्ट दृष्टिकोण का तर्क नव–उदारवादी कार्यसूची या एजेंडा द्वारा समर्थित है, जो कि वैश्वीकरण को मुक्त बाजार के संदर्भ में देखता है। वैश्विक बाजार और मुक्त व्यापार राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए खतरा पैदा करते हैं, जो कि राजनीतिक संगठन की प्राथमिक इकाई के रूप में राष्ट्र राज्य को समाप्त कर देता है।

उदारवादी प्रगतिशील लोग भी आर्थिक उदारीकरण के विचार का समर्थन करते हैं, परंतु वे इस तथ्य को भी स्वीकार करते हैं कि यदि समानता के मुद्दों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है तो यह दुधारी तलवार के रूप में कार्य कर सकता है। ग्लोबलिस्ट यह स्पष्ट रूप से मानते हैं कि वैश्वीकरण एक अधिक विविध समाज बनाता है, परंतु वह वैश्विक पर्यावरण के प्रदूषण के खतरों को भी प्रस्तुत करता है।

सकारात्मक ग्लोबलिस्ट यह तर्क देते हैं कि यदि हम सभी अपने उपभोग के अस्थिर स्तर को कम करने के लिए कुछ जिम्मेदारी ले लें तो प्रदूषण को कम किया जा सकता है। वे प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए नई प्रौद्योगिकियों के विकास की एक महत्वपूर्ण भूमिका पाते हैं। कुल मिलाकर ग्लोबलिस्ट यह मानते हैं कि वैश्वीकरण का विरोध करने का कोई भी प्रयास विफलता के लिए अभिशप्त होगा। वैश्वीकरण किसी न किसी प्रकार से एक अधिक अनिश्चित और विविध दुनिया का निर्माण कर रहा है। प्रत्येक दृष्टिकोण में उसकी खामियाँ होती हैं और उसके प्रत्येक तर्क के लिए कुछ मान्य बिंदु होते हैं। प्रत्येक तर्क मान्य हो सकता है, जो कि इस बात पर निर्भर करेगा कि आप उसे किस दृष्टि से देखते हैं और उसकी किस बात पर विश्वास करते हैं, परंतु हर व्यक्ति को प्रत्येक परिणाम पर प्रत्येक व्यक्ति की अपनी राय जाननी होगी।

13.5 वैश्वीकरण का प्रभाव

विस्थापन (delocalization) के प्रभाव को न केवल व्यक्तियों बल्कि संस्थाओं ने भी महसूस किया है। इसका एक महत्वपूर्ण कारण राष्ट्रीय सरकारों की अपनी अर्थव्यवस्थाओं को निर्देशित और प्रेरित करने की शक्ति में गिरावट रहा है। उदाहरण के लिए, अमेरिका और जापान की आर्थिक गतिविधियों में बदलाव विश्व भर में महसूस किए जाते हैं। वैश्वीकरण के प्रभाव को इस हद तक महसूस किया जाता है कि हर जगह नीतियाँ अब अनिवार्य रूप से बाजार संचालित होती हैं। इसका अर्थ है कि यदि सरकारें अपनी सत्ता कायम रखना चाहती हैं तो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार शक्तियों के दबाव के अनुकूल अपनी राष्ट्रीय नीतियों का प्रबंधन करने की क्षमता बढ़ानी होगी।

वैश्वीकरण की विद्यमानता में बहुराष्ट्रीय निगमों की कार्रवाई का स्तर और कार्यक्षेत्र बढ़ रहा है, परंतु वैश्वीकरण की जटिलताओं पर उनका नियंत्रण सीमित ही है। वैश्विक बाजार निगमों के लिए संप्रभु राज्यों के पिछले कार्यों का बहाना करना असंभव बना देता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने वैश्वीकरण के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, फिर भी यह ध्यान रखना आवश्यक है कि वैश्वीकरण की गतिशीलता पर उनका जितना नियंत्रण है, वह पर्याप्त नहीं है।

13.5.1 वैश्वीकरण और श्रम

बांग्लादेश जैसा कोई भी गरीब देश जिसका सकल घरेलू उत्पाद निम्न हो, पारंपरिक कृषि या खनिज उत्पादों के निर्यात की तुलना में विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात पर निर्भर होता है। किसी विकासशील देश में ऐसे निर्यात माल के निर्माण के लिए अथक परिश्रम करने वाले श्रमिकों को बहुत कम मजदूरी दी जाती है, विशेष रूप से उन्नत–देश मानकों के अनुसार। ऐसी खराब अर्थव्यवस्थाओं में इन श्रमिकों के पास कुछ ही अच्छे विकल्प होते हैं। यहाँ तक कि कई मामलों में कार्य की परिस्थितियाँ भी बेहद खराब होती हैं।

सक्रियतावादियों का तर्क है कि कम मजदूरी और खराब कामकाजी परिस्थितियों ने दिखाया है कि वैश्वीकरण विकासशील देशों में श्रमिकों की कोई मदद नहीं कर रहा है। उदाहरण के लिए, जापान वियतनाम और इंडोनेशिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाला अग्रणी देश है। वियतनाम जैसे देशों में युवा आबादी, निम्न सकल घरेलू उत्पाद और सस्ता श्रम है, जो कि इन देशों को विकसित देशों के उपयोग के लिए एक बहुत ही आकर्षक विकल्प बनाता है।

जापान में उच्च वेतन वाले श्रमिकों के स्थान पर वियतनाम में कम वेतन वाले श्रमिकों को रखना नियोक्ताओं के लिए आसान होता है। तदनुसार वैश्वीकरण ने दोनों देशों के कर्मचारियों को आहत किया। फिर भी कुछ लोगों का तर्क है कि वियतनाम जैसे देशों में मजदूरी और काम करने की स्थिति भयावह लग सकती है, परंतु वे ऐसे देशों में उपलब्ध विकल्पों में सुधार का प्रतिनिधित्व करते हैं।

विदेशी कारखानों में रोजगार के बढ़ने से संकेत मिलता है कि श्रमिकों ने अपने सामने मौजूद अन्य विकल्पों की तुलना में वहाँ मिलने वाली नौकरियों को प्राथमिकता दी। वैश्वीकरण के पक्ष में मानक तर्क यह है कि विकासशील देशों में श्रमिकों द्वारा अर्जित कम मजदूरी के बावजूद, वैश्वीकरण होने पर ये श्रमिक उससे बेहतर स्थिति में हैं जैसे कि वे वैश्वीकरण न होने पर होते। इसका कारण यह है कि पूँजी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गतिशील है, जबकि श्रम नहीं है; और यह भी कि यह गतिशीलता पूँजीपतियों को सौदेबाजी का लाभ देती है।

13.5.2 वैश्वीकरण और पर्यावरण

वैश्वीकरण के विरुद्ध शिकायतें श्रम संबंधी मुद्दों से कहीं अधिक हैं। कई आलोचकों का तर्क है कि वैश्वीकरण पर्यावरण के लिए खराब है। यह सत्य है कि विकासशील देशों के निर्यात उद्योग में पर्यावरण मानक उन्नत देशों के उद्योगों की तुलना में बहुत निम्न हैं। उन्नत देशों के बाजारों में माल उपलब्ध कराने के लिए काफी हद तक पर्यावरणीय क्षति

हुई है। उदाहरण के लिए, जापानी और पश्चिमी बाजारों में बिक्री के लिए वन उत्पादों का उत्पादन करने के लिए दक्षिण–पूर्व एशियाई जंगलों की भारी कटाई की जाती है। किंतु दूसरी ओर, वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ भागीदारी न करने के इच्छुक देशों की ''अंतर्मुखी'' नीतियों के नाम पर हुई पर्यावरणीय क्षति के उदाहरण भी हैं।

ब्राजील में एक घरेलू नीति के चलते, जो कि अभ्यंतर के विकास में सब्सिडी देती है, कई वर्ग मील वर्षा वनों का विनाश हुआ है। इस नीति का वैश्वीकरण से कोई लेना–देना नहीं है और वास्तव में उन वर्षों के दौरान शुरू हुआ था जब ब्राजील अंतर्मुखी विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा था।

इन दिनों इस बात पर बहस चल रही है कि क्या व्यापार समझौतों में पर्यावरण मानकों को शामिल किया जाना चाहिए। इस तरह के समझौतों के दो पक्ष ये हैं कि इस प्रकार के समझौतों से पर्यावरण में कुछ ऐसे सुधार हो सकते हैं जिनसे सभी को फायदा होगा और व्यापार समझौतों के लिए पर्यावरण मानकों को जोड़ने से गरीब देशों में संभावित निर्यात उद्योग बंद हो जाएँगे क्योंकि उनके लिए पश्चिमी मानकों को बनाए रखना महँगा पड़ेगा।

व्यापार और पर्यावरण का यह परस्पर हस्तक्षेप कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विवादों में पर्यावरणीय मुद्दे उत्तरोत्तर बढ़ती भूमिका निभा रहे हैं। कुछ वैश्वीकरण विरोधी सक्रियतावादियों का दावा है कि बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से पर्यावरण को निरंतर हानि पहुँचती है। कुछ का यह भी दावा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते और विश्व व्यापार संगठन की भूमिका पर्यावरणीय कार्रवाई में बाधा डालने का प्रभाव है। अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्री यह नहीं मानते हैं कि व्यापार समझौते देशों को अभिज्ञात पर्यावरण नीतियों से रोकते हैं।

13.5.3 वैश्वीकरण और विश्व की गरीबी

वैश्वीकरण से सभी राष्ट्रों को लाभ नहीं हुआ और इस कारण वैश्वीकरण पर प्रायः विश्व की गरीबी बढ़ाने का आरोप लगाया जाता है। दूसरा दृष्टिकोण यह है कि वैश्वीकरण के बिना विश्व की गरीबी शायद और भी अधिक व्यापक होगी। ऐसा लगता है कि विश्व के कुछ सबसे गरीब देश, जैसे कि उप–सहारा अफ्रीका में, पीछे छूट गए हैं। ऐसे क्षेत्रों में गरीबी का कारण वैश्वीकरण नहीं बल्कि सूखा, अकाल, आंतरिक कलह, युद्ध और एड्स हैं। तथापि, यहाँ वैश्वीकरण ने वर्धित दक्षता और उदारता के लाभों को नहीं फैलाया, जो कि वैश्वीकरण के साथ सभी देशों के लिए समान रूप से और न्यायसंगत रूप से आते हैं। वैश्वीकरण के बिना विश्व में गरीबों की संख्या कहीं अधिक होती। बहरहाल, अभी भी बहुत–से लोग गैर–वैश्वीकृत देशों में रह रहे हैं, जो कि भीषण गरीबी की मार झेल रहे हैं।

अपनी प्रगति की जाँच कीजिए 1

नोटः i) अपने उत्तरों के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग करें।
ii) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपनी प्रगति की जाँच करें।

1) वैश्वीकरण के लिए अर्थशास्त्रिक दृष्टिकोण क्या दर्शाता है? चर्चा करें।

.....

.....

.....

2) वैश्वीकरण के प्रति परिवर्तनवादी दृष्टिकोण ग्लोबलिस्ट दृष्टिकोण से किस प्रकार भिन्न है? स्पष्ट करें।

.....

.....

.....

3) पर्यावरण पर वैश्वीकरण के प्रभाव की व्याख्या करें।

.....

.....

.....

.....

4) वैश्वीकरण की अवधारणा पर चर्चा करें।

.....

.....

.....

.....

13.6 सारांश

इकाई में चर्चा से स्पष्ट हुआ कि वैश्वीकरण को समझना एक कठिन अवधारणा है। इसके विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण हैं और उनमें से प्रत्येक परिघटना को स्वयं के ढाँचे के भीतर परिभाषित करने का प्रयास है। एक और भी पेचीदा मुद्दे में स्थानीय और राष्ट्रीय संस्कृतियों पर वैश्वीकरण का प्रभाव शामिल है। यह असंदिग्ध रूप से सत्य है कि बाजारों के बढ़ते एकीकरण ने विश्व भर की संस्कृतियों का एकरूपीकरण किया है। विश्व भर में यह प्रवृत्ति तेजी से बढ़ती जा रही है कि लोग अब एक जैसे कपड़े पहनते हैं, एक–सा ही खाना खाते हैं, एक–सा ही संगीत सुनते हैं तथा एक ही तरह की फिल्में और टीवी शो देखते हैं। फिर भी कुल मिलाकर वैश्वीकरण की प्रक्रिया पर्यावरण को प्रभावित करती है।

इकाई में विभिन्न परिप्रेक्ष्यों और दृष्टिकोणों पर विस्तार से चर्चा की गई, जो कि वैश्वीकरण की अवधारणा के पीछे निहित विचार की व्यापक रेखा को इंगित करते हैं। ये परिप्रेक्ष्य और दृष्टिकोण नीति–निर्माण और वैश्वीकरण प्रक्रिया के परिणामों को प्रभावित करते हैं। हम कह सकते हैं कि वैश्विक परिवर्तनों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए एक सकारात्मक और संतुलित दृष्टिकोण का अर्थ होगा –स्थानीय और वैश्विक को समेकित करना क्योंकि ये दोनों ही वैश्वीकरण के अपरिहार्य तत्व हैं।

13.7 शब्दावली

वैश्वीकरण वे सभी प्रक्रियाएँ जिनके द्वारा विश्व भर के लोग एक एकल विश्व समाज में समाविष्ट हैं।

अर्थशास्त्रिक परिप्रेक्ष्य अर्थशास्त्रिक परिप्रेक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय की बढ़ती प्रायिकता, विभिन्न देशों के बीच अधिकाधिक परस्पर निर्भरता और उनके एकीकरण की सुविधा में वृद्धि पर बल देता है।

विश्व–नागरिक परिप्रेक्ष्य विश्वव्यापी दृष्टिकोण इस सिद्धांत पर बल देता है कि सभी मनुष्य एक वैश्विक समुदाय के सदस्य हैं।

परिवर्तनवादी दृष्टिकोण राष्ट्र राज्य शक्तिशाली बना रहता है और जो भी चुनौतियाँ होती हैं उनका पुनर्गठन, सुधार और वैश्विक शासन के नए रूपों को समायोजित करके सामना किया जा सकता है।

अंतर्राष्ट्रीयवादी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीयवादियों का मानना है कि अधिकांश आर्थिक और सामाजिक गतिविधियाँ वैश्विक स्तर पर नहीं बल्कि क्षेत्रीय रूप से की जाती हैं।

13.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें

जोआन चिरिको (2013), *ग्लोबलाइजेशन : प्रोस्पेक्टस एंड प्रॉब्लम्स*, पहला संस्करण, सेज पब्लिकेशन्स।

जॉर्ज रिट्जर (2011), *ग्लोबलाइजेशन : ए बेसिक टेक्स्ट*, विले–ब्लैकवेल।

13.9 बोध प्रश्नों के उत्तर अथवा संकेत

बोध प्रश्न 1

1) (पाठांश 13.3.1 देखें) अर्थशास्त्रिक परिप्रेक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय की बढ़ती प्रायिकता, विभिन्न देशों के बीच अधिक परस्पर निर्भरता और उनके एकीकरण की सुविधा में वृद्धि पर जोर देता है।

2) (संदर्भ पाठांश 13.4) परिवर्तनवादियों के अनुसार राष्ट्र राज्य शक्तिशाली बना रहता है और जो भी चुनौतियाँ आती हैं उनका पुनर्गठन, सुधार और वैश्विक शासन के नए

रूपों को समायोजित करके सामना किया जा सकता है। ग्लोबलिस्ट दृष्टिकोण का तर्क नव–उदारवादी एजेंडा द्वारा समर्थित है, जो कि वैश्वीकरण को मुक्त बाजार के संदर्भ में देखता है। वैश्विक बाजार और मुक्त व्यापार राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए खतरा पैदा करते हैं, जो कि राष्ट्र राज्य को राजनीतिक संगठन की प्राथमिक इकाई के रूप में समाप्त कर देता है।

3) (पाठांश 13.5.2 देखें) यह सच है कि विकासशील देशों के निर्यात उद्योग में पर्यावरण मानक उन्नत देशों के उद्योगों की तुलना में बहुत निम्न हैं। उन्नत देशों के बाजारों में माल उपलब्ध कराने में काफी हद तक पर्यावरणीय क्षति हुई है।

4) (पाठांश 13.2 देखें) वैश्विक परिवर्तन की प्रकृति की विभिन्न व्याख्याएँ जो इस वाद–विवाद के परिणामस्वरूप सामने आती हैं, सामाजिक विज्ञान की विभिन्न विद्याशाखाओं के परिप्रेक्ष्य से वैश्वीकरण पर विभिन्न दृष्टिकोणों को दर्शाती हैं। वैश्वीकरण पर अर्थशास्त्रियों, समाजशास्त्रियों और राजनीतिक वैज्ञानिकों के विचार वैश्वीकरण के विभिन्न आयामों पर जोर देते हैं। वैश्वीकरण के बारे में इस प्रकार के विचारों के कारण इस पदबंध का निर्धारण और मूल्यांकन अलग तरह से किया जाता है। वैश्वीकरण की अवधारणा के उद्‌भव और उसके सामाजिक–विज्ञान प्रयोग पर चर्चा करें।